

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2017 — माघ 11, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-1/तीन (दो)/न.पा./व्यव लेखा/2016/2013

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2017

1. श्रीमती अम्बिका यदु, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर, छ.ग.
2. श्रीमती चमेली साहू, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर, छ.ग.
3. श्रीमती जरीना बेगम, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर, छ.ग.
4. श्रीमती जैतून कुरैशी, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर, छ.ग.
5. श्रीमती मोमिना खातून, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर, छ.ग.
6. श्रीमती ललीता देवांगन, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर, छ.ग.
7. श्रीमती शहिदा बेगम, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर, छ.ग.
8. श्रीमती सीमा यादव, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर, छ.ग.
9. श्रीमती सुनीता देवांगन, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर, छ.ग.
10. श्रीमती सुमित्रा देवांगन, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर, छ.ग.
11. श्रीमती हलीमा खातून, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2015, नगर पालिक निगम, बीरगांव, जिला रायपुर, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अंतर्गत)

पारित दिनांक 31 जनवरी, 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 20 अप्रैल 2016 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम बीरगांव के महापौर पद के लिये आयोजित आम निर्वाचन 2015 में कुल 16 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 19 नवम्बर 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 20 अप्रैल 2016 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया है कि नगर पालिक

निगम बीरगांव के आम निर्वाचन 2015 में महापौर पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थीगण श्रीमती हलीमा खातून, श्रीमती शहिदा बेगम, श्रीमती जरीना बेगम, श्रीमती जैतून कुरैशी, श्रीमती मोमिना खातून, श्रीमती सुमित्रा देवांगन एवं श्रीमती ललिता देवांगन द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है एवं श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती चमेली साहू, श्रीमती सीमा यादव एवं श्रीमती सुनीता देवांगन ने दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को दाखिल किया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की अंतिम तिथि 18 दिसम्बर 2015 को शासकीय अवकाश के कारण अंतिम तिथि 21 दिसम्बर 2015 निर्धारित की गई है।

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका), रायपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में चूंकि नियमानुसार निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के निर्धारण की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा के दिनांक को छोड़कर 30 दिनों तक करने से अंतिम तिथि 19 दिसम्बर 2015 होती है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती चमेली साहू, श्रीमती जरीना बेगम, श्रीमती जैतून कुरैशी, श्रीमती मोमिना खातून, श्रीमती ललिता देवांगन, श्रीमती शहिदा बेगम, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती सुनीता देवांगन, श्रीमती सुमित्रा देवांगन एवं श्रीमती हलीमा देवांगन को दिनांक 11 मई 2016 को अधिनियम की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-क एवं 14-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहें तथा क्यों उन उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 14-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिक निगम का महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए।

4. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थीगण श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती शहिदा बेगम, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती सुनीता देवांगन, श्रीमती जरीना बेगम एवं श्रीमती हलीमा खातून को दिनांक 20.5.2016 को एवं श्रीमती चमेली साहू को दिनांक 18.5.2016 को सम्यक रूप से तामील की गई। अभ्यर्थीगण श्रीमती जैतून कुरैशी, श्रीमती मोमिना खातून, श्रीमती ललिता देवांगन एवं श्रीमती सुमित्रा देवांगन को कारण बताओ सूचना तामील नहीं होने के कारण पुनः दिनांक 2.9.2016 को कारण बताओ सूचना जारी की गई जो अभ्यर्थीगण श्रीमती जैतून कुरैशी, श्रीमती मोमिना खातून एवं श्रीमती सुमित्रा देवांगन को दिनांक 8.9.2016 एवं श्रीमती ललिता देवांगन को दिनांक 9.9.2016 को तामील की गई। कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थियों श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती चमेली साहू एवं श्रीमती सुनीता देवांगन द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया।

5. अभ्यर्थीगण श्रीमती हलीमा खातून, श्रीमती शहिदा बेगम, श्रीमती जरीना बेगम, श्रीमती जैतून कुरैशी, श्रीमती

मोमिना खातून, श्रीमती सुमित्रा देवांगन एवं श्रीमती ललिता देवांगन को कारण बताओ सूचना तामील होने के पश्चात् भी अभ्यर्थीगण द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया । ऐसी स्थिति में यह माना गया कि अभ्यर्थीगण श्रीमती हलीमा खातून, श्रीमती शहिदा बेगम, श्रीमती जरीना बेगम, श्रीमती जैतून कुरैशी, श्रीमती मोमिना खातून, श्रीमती सुमित्रा देवांगन एवं श्रीमती ललिता देवांगन को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

6. अभ्यर्थी श्रीमती अम्बिका यदु ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब दिनांक 24.5.2016 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु नोडल अधिकारी व्यय अन्वेक्षण स्थानीय निर्वाचन 2015 जिला रायपुर से सम्पर्क किया गया । उन्हें मौखिक रूपसे सूचित किया गया कि दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को तृतीय शनिवार एवं दिनांक 20 दिसम्बर 2015 को रविवार अवकाश होने के कारण आगामी कार्यदिवस दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा विहित अवधि में प्रस्तुत करना मान्य करते हुए स्वीकार किया जायेगा । तदनुसार उनके द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को नोडल अधिकारी व्यय अन्वेक्षण स्थानीय निर्वाचन 2015 जिला रायपुर के पास निर्वाचन व्यय लेखा जमा कर उसकी पावती प्राप्त कर ली गई । उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि नगरपालिक अधिनियम, 1956 तथा संबंधित निर्वाचन नियम के अतिरिक्त धारा 4 म्याद अधिनियम 1963 के अनुसार विहित अवधि के अंतिम दिन अवकाश होने की अवस्था में आगामी कार्य दिवस पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है । इस प्रकार उनके द्वारा विहित समयावधि के अन्दर ही निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया है । अतः उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को मान्य करते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे ।

7. अभ्यर्थी श्रीमती सीमा यादव ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब दिनांक 24 मई 2016 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि उन्होंने अपना निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 15 दिसम्बर 2015 को नगर निगम बीरगांव में प्रस्तुत कर दिया था जिसे 4 दिन बाद वहां के भृत्य के हस्ते वापस यह कहते हुए किया गया कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं जिला निर्वाचन कार्यालय में जाकर जमा करना होगा । इस पर उनके द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को नोडल अधिकारी व्यय अन्वेक्षण स्थानीय निर्वाचन 2015 जिला रायपुर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त की गई । जवाब के साथ पावती भी संलग्न की गई है ।

8. अभ्यर्थी श्रीमती सुनीता देवांगन ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब दिनांक 2 जून 2016 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि उन्होंने अपना निर्वाचन व्यय लेखा चूंकि दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को सार्वजनिक अवकाश घोषित होने एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को तृतीय

शनिवार एवं दिनांक 20 दिसम्बर 2015 को रविवार अवकाश होने के कारण आगामी कार्यदिवस दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को विहित अवधि में नोडल अधिकारी व्यय अन्वेक्षण स्थानीय निर्वाचन 2015 जिला रायपुर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त की गई। जवाब के साथ पावती भी संलग्न की गई है।

9. अभ्यर्थी श्रीमती चमेली साहू ने कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब दिनांक 2 जून 2016 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु विहित अधिकारी के पास गये तो कार्यालय में कोई नहीं था। कार्यालय सार्वजनिक अवकाश होने के कारण बन्द था। अतः उनके द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को विहित अवधि में नोडल अधिकारी व्यय अन्वेक्षण स्थानीय निर्वाचन 2015 जिला रायपुर जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त की गई। जवाब के साथ पावती भी संलग्न की गई है।

10. अभ्यर्थीगण श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती चमेली साहू एवं श्रीमती सुनीता देवांगन द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) रायपुर का अभिमत प्राप्त किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) रायपुर ने ज्ञापन दिनांक 141/स्था./निर्वा./2016 दिनांक 19 जुलाई 2016 में अभिमत दिया है कि अभ्यर्थीगण श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती चमेली साहू एवं श्रीमती सुनीता देवांगन द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को गुरु घासीदास जयंती एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को तृतीय शनिवार एवं दिनांक 20 दिसम्बर 2015 को रविवार अवकाश होने के कारण आगामी कार्यदिवस दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को जमा किया गया। विलम्ब विधिक रूपसे न्यायोचित होने के कारण क्षमा योग्य होने का उल्लेख किया है। अभिमत में निर्वाचन संदर्शिका के अध्याय 19 के बिन्दु 7(11) का सन्दर्भ देते हुए तथा तत्संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायपुर द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर 2015 को अनुमोदित नोटसूची की छाया प्रति संलग्न की गई जिसमें समयावधि की आखिरी दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को सार्वजनिक अवकाश एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को तृतीय शनिवार एवं दिनांक 20 दिसम्बर 2015 को रविवार अवकाश होने के कारण आगामी कार्यदिवस दिनांक 21 दिसम्बर 2015 तक निर्वाचन व्यय लेखा तक स्वीकार किया जाना आदेशित किया गया था। उनके द्वारा परिशिष्ट 36 में प्रेषित जानकारी को नियमानुसार सही होने का उल्लेखित किया गया है।

11. श्री एवज देवांगन, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क.31, नगर निगम बीरगांव, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में दिनांक 23.11.2016 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुख्य रूपसे आवेदक ने अम्बिका यदु सहित चार अन्य प्रत्याशियों द्वारा दिनांक 21.12.2015 को जमा किये गये निर्वाचन व्यय लेखा, के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिशिष्ट 36 में आयोग कार्यालय को प्रेषित प्रतिवेदन को गलत है, का उल्लेख करते हुए लेख किया है कि दिनांक 19.12.2016 को सार्वजनिक अवकाश होने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी ने नहीं दिया

है। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.8.2016 एवं शासन के सार्वजनिक अवकाश की छायाप्रति संलग्न कर छै: माह के अन्दर कार्रवाई करने के पूर्व उसे भी अंतिम सुनवाई के लिए तर्क-वितर्क रखने का अवसर प्रदान कर अपना पक्ष रखने तथा प्रत्याशियों पर नियमानुसार 14(क), 14(ख), 14(ग), के अन्तर्गत बर्खास्तगी की कार्यवाही कर अयोग्य घोषित करने का निवेदन किया गया है।

12. अभ्यर्थियों श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती चमेली साहू एवं श्रीमती सुनीता देवांगन द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में उन्हें सुनवाई हेतु दिनांक 28 सितम्बर 2016 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया निर्धारित सुनवाई दिनांक को अभ्यर्थी श्रीमती अम्बिका यदु की ओर से अधिवक्ता सुधीर तिवारी ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत कर पक्ष समर्थन हेतु समय प्रदान करने का आग्रह किया। अभ्यर्थीगण श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती चमेली साहू एवं श्रीमती सुनीता देवांगन सुनवाई हेतु जारी सूचना प्राप्ति के उपरान्त उपस्थित नहीं होने के कारण यह मानकर की उक्त अभ्यर्थियों को अपने पक्ष समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, दिनांक 28 सितम्बर 2016 को उनके विरुद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्रवाई की गई।

13. अभ्यर्थी श्रीमती अम्बिका यदु एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर द्वारा सुनवाई में दिनांक 24 नवम्बर 2016 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। श्रीमती अम्बिका यदु ने अपने शपथपत्र में उल्लेख किया कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा पूर्ण रूपसे तैयार कर अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से जमा करने हेतु दिनांक 17 दिसम्बर 2015 को नोडल अधिकारी व्यय अन्वेषण स्थानीय निर्वाचन 2015 जिला रायपुर के पास भेजा था। जिसमें व्हाउचरों की कम संख्या एवं रसीद में नंबर दर्ज नहीं होने के कारण जमा नहीं लिया गया तथा त्रुटि सुधार कर आगामी तिथि को प्रस्तुत करने को कहा गया। उनके निर्वाचन अभिकर्ता दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने गये तो उक्त दिनांक को शासकीय अवकाश होने से कार्यालय बंद था तथा दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को तृतीय शनिवार एवं 20 दिसम्बर 2015 को रविवार होने से कार्यालय बंद था, संबंधी सूचना कार्यालय के बाहर चस्पा था। तत्संबंध में सूचना के अधिकार में कार्यालयीन आदेश पत्रिका की प्रति उनके द्वारा प्राप्त कर उसकी छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत की गई। अतः उनके द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर पावती प्राप्त की गई जिसकी छाया प्रति संलग्न की गई है। अभ्यर्थी श्रीमती अम्बिका यदु की ओर से उनके अधिवक्ता श्री सुधीर तिवारी द्वारा आयोग में दिनांक 30 जनवरी 2017 को उपस्थित होकर लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 की छायाप्रति संलग्न प्रस्तुत कर अध्याय 4 में उल्लेखित "सार्वजनिक अवकाश" से संबंधित टिप्पणी की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

14. अभ्यर्थी श्रीमती अम्बिका यदु के निर्वाचन अभिकर्ता श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर ने शपथपत्र दिनांक 24 नवम्बर

2015 में उल्लेख किया है कि वे दिनांक 17 दिसम्बर 2015 को नोडल अधिकारी व्यय अन्वेक्षण स्थानीय निर्वाचन 2015 जिला रायपुर के पास उपस्थित हुए थे। वहां व्हाउचरों की कम संख्या एवं रसीद में नंबर दर्ज नहीं होने के कारण जमा नहीं लिया गया तथा त्रुटि सुधार कर आगामी तिथि को प्रस्तुत करने को कहा गया। जिसकी जानकारी उन्होंने अभ्यर्थी अम्बिका यदु को प्रदान की थी। वे पुनः दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने उपस्थित हुए तो उन्हें दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को शासकीय अवकाश होने से कार्यालय बंद है तथा दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को तृतीय शनिवार एवं 20 दिसम्बर 2015 को रविवार होने से कार्यालय बंद था, संबंधी सूचना कार्यालय के बाहर चسपा थी। उन्होंने नोडल अधिकारी से बात की तो उनके द्वारा उक्त दिनाकों को कार्यालय बन्द होने तथा निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तत्संबंध में सूचना के अधिकार में कार्यालयीन आदेश पत्रिका की प्रति उनके द्वारा प्राप्त कर उसकी छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत की गई। अतः उनके द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को कार्यालय खुलने पर नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत कर पावती प्राप्त की गई, जिसकी छाया प्रति संलग्न की गई है।

15. अभ्यर्थी श्रीमती अम्बिका यदु द्वारा प्रतिउत्तर दिनांक 12 जनवरी 2017 प्रस्तुत कर श्री एवज देवांगन के शिकायत पत्र दिनांक 12 जनवरी 2017 में उल्लेखित आपत्ति कि, नगरपालिक अधिनियम 1956 की धारा 14 (ख) के अन्तर्गत महापौर पद के प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसरों के लिए बने हस्तपुस्तिका (निर्वाचन संदर्शिका) निर्वाचन व्यय का लेखा संशोधित नियमों के आधार पर मतगणना के बाद के दिनों से 30 दिनों के भीतर अपना व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना रहता है। इस हिसाब से 30 दिन 19 दिसम्बर 2015 को पूर्ण होता है, न कि 18 दिसम्बर 2015 को और दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को कोई भी प्रकार का अवकाश शासन के सार्वजनिक अवकाश की सूची में नहीं था लेकिन श्रीमती अम्बिका यदु ने समय-सीमा में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत न कर दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को प्रस्तुत किया है। श्री देवांगन द्वारा अपने शिकायत पत्र में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने की आखिरी तारीख बताकर और उस दिन सार्वजनिक अवकाश बताना गलत है, का उल्लेख करते हुए श्रीमती अम्बिका यदु को महापौर पद से निर्हित कर बर्खास्त करने का निवेदन किया है, को भ्रमक होने का उल्लेख करते हुए अस्वीकार किया गया है। अभ्यर्थी श्रीमती अम्बिका यदु द्वारा अपने जवाब एवं शपथपत्र की पुष्टि में कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी रायपुर एवं उप कोषालय अधिकारी आरंग जिला रायपुर के पत्रों जिनमें दिनांक 18, 19 एवं 20 दिसम्बर को सार्वजनिक अवकाश होने तथा कार्यालय बन्द रहने का उल्लेख है, संलग्न किया गया है।

16. प्रकरण से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) रायपुर ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थीगण श्रीमती हलीमा खातून, श्रीमती शहिदा बेगम, श्रीमती

जरीना बेगम, श्रीमती जैतून कुरैशी, श्रीमती मोमिना खातून, श्रीमती सुमित्रा देवांगन एवं श्रीमती ललिता देवांगन द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार एवं उसके पश्चात् आज पर्यन्त निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है एवं श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती चमेली साहू, श्रीमती सीमा यादव एवं श्रीमती सुनीता देवांगन ने दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को दाखिल किया है। अधिनियम की धारा 14-क (1) निम्नानुसार है:

“14-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा.- (1) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा।”

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14-क (1) की अपेक्षानुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 14-ख निम्नानुसार है:

“धारा 14-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना.- महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा।”

अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से तीस दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्घिष्ट किया गया है। अतः उक्त व्यय लेखा जिलानिर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था।

17. 1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) रायपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बन्धित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम बीरगांव के महापौर पद के आम निर्वाचन 2015 में भाग लेने वाली अभ्यर्थीगण श्रीमती हलीमा खातून, श्रीमती शहिदा बेगम, श्रीमती जरीना बेगम, श्रीमती जैतून कुरैशी, श्रीमती मोमिना खातून, श्रीमती सुमित्रा देवांगन एवं श्रीमती ललिता देवांगन द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति

से निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब/अभ्यावेदन आज पर्यन्त प्रस्तुत किया गया। इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी। अतः मुझे यह समाधान हो गया है अभ्यर्थी श्रीमती हलीमा खातून, श्रीमती शहिदा बेगम, श्रीमती जरीना बेगम, श्रीमती जैतून कुरैशी, श्रीमती मोमिना खातून, श्रीमती सुमित्रा देवांगन एवं श्रीमती ललिता देवांगन प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं।

2 अभ्यर्थीगण श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती चमेली साहू एवं श्रीमती सुनीता देवांगन ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपने लिखित जवाब प्रस्तुत किये गये जिसके अनुसार इन अभ्यर्थियों ने दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा नोडल अधिकारी व्यय अन्वेक्षण स्थानीय निर्वाचन 2015 जिला रायपुर के पास दाखिल किया गया है तथा उसकी पावती भी जवाब के साथ संलग्न की है।

3 श्री एवज देवांगन चन्द्रशेखर आजाद वार्ड क.31, नगर निगम बीरगांव, रायपुर द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 23.11.2016 में उल्लेख करते हुए कि प्रश्नाधीन प्रकरण में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 19 दिसम्बर 2015 थी एवं इस तारीख को सार्वजनिक अवकाश होना शासन की अवकाश सूची 2015 में अंकित नहीं है अतः अभ्यर्थी श्रीमती अम्बिका यदु को नगर पालिक निगम बीरगांव के महापौर पद से बर्खास्त करने एवं 5 वर्ष के लिए निरहित किये जाने तथा प्रकरण की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने एवं तर्क प्रस्तुत करने का भी निवेदन किया गया। श्री एवज देवांगन को प्रकरण के संबंध में तर्क प्रस्तुत करने एवं सुनवाई के समय उपस्थित होने की अनुमति दी गई। श्री एवज देवांगन सुनवाई के समय उपस्थित रहे। श्री एवज देवांगन द्वारा एक और आवेदन प्रस्तुत कर उसमें मुख्य रूपसे लेख किया गया कि निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखिरी तारीख 19 दिसम्बर 2015 थी एवं इस तारीख को सार्वजनिक अवकाश होना शासन की अवकाश सूची 2015 में अंकित नहीं है, के अतिरिक्त अन्य कोई नया साक्ष्य/तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

4 अभ्यर्थीगण श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती चमेली साहू एवं श्रीमती सुनीता देवांगन द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 के पूर्व दिनांक 18, 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 को भी निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने हेतु नोडल अधिकारी व्यय लेखा से सम्पर्क किया गया परन्तु दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य में शासकीय अवकाश एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2015 तथा 20 दिसम्बर 2015 को क्रमशः तृतीय शनिवार एवं रविवार का शासकीय अवकाश था। जिसकी सूचना कार्यालय मे चरप्पा की गई थी। इसकी पुष्टि अभ्यर्थी श्रीमती अम्बिका यदु के निर्वाचन अभिकर्ता श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर के

शपथपत्र दिनांक 24.11.2015, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वे निर्वाचन व्यय लेखा जमा करने दिनांक 17 दिसम्बर 2015 को नोडल अधिकारी व्यय अन्वेषण स्थानीय निर्वाचन 2015 जिला रायपुर के पास उपस्थित हुए थे तथा कुछ त्रुटिसुधार हेतु उक्त दिनांक को जमा नहीं लिया गया तथा आगामी तिथि को त्रुटिसुधार कर जमा करने को कहा गया, दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को कार्यालय में उपस्थित होने पर जानकारी हुई कि दिनांक 18, 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 को शासकीय अवकाश होने से कार्यालय बन्द है जिसकी सूचना कार्यालय के बाहर चस्पा थी, से होती है ।

5. अभ्यर्थी श्रीमती चमेली साहू के जवाब की कंडिका 2 में उल्लेखित है कि दिनांक 18.12.2015 को विहित अधिकारी के पास जमा करने गये तो कार्यालय में कोई नहीं थे तथा कार्यालय बन्द थे, से तथा अभ्यर्थी अम्बिका यदु के निर्वाचन अभिकर्ता श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी एवं जनसूचना अधिकारी जिला कोषालय रायपुर तथा कार्यालय उप जिला कोषालय अधिकारी आरंग जिला रायपुर के पत्र क्रमशः दिनांक 12.1.17 एवं 16.1.2017 की प्रस्तुत की गई छायाप्रति (प्रदर्श-पीपी 2, पीपी 3 एवं पीपी 4) जिसमें उल्लेख है कि दिनांक 18.12.2015, दिनांक 19.12.2015 एवं 20.12.2015 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण कोषालय का कार्यालयीन कार्य पूर्ण रूप से बन्द था एवं किसी प्रकार का शासकीय लेन-देन नहीं किया गया से भी इसकी पुष्टि होती है ।

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) रायपुर के पत्र दिनांक 19.7.2016 में दिये गये अभिमत एवं उसके साथ संलग्न निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कार्यालय की नोटसशीट आदेश दिनांक 16.12.2015 की छायाप्रति (प्रदर्श-पीपी 1) से भी दिनांक 18, 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 को शासकीय अवकाश होने की पुष्टि होती है ।

7. श्री एवज देवांगन की आपत्ति है कि दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को तृतीय शनिवार को कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं था इसलिए निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 दिसम्बर 2015 थी । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका), रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 20 अप्रैल 2016 एवं पत्र दिनांक 19.7.2016 में दिये गये अभिमत के अनुसार दिनांक 18 दिसम्बर 2015 को गुरु घासीदास जयंती का शासकीय अवकाश, दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को तृतीय शनिवार होने से छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय अवकाश तथा दिनांक 20 दिसम्बर 2015 को रविवार का शासकीय अवकाश होने के कारण कार्यालय बन्द रहा । यद्यपि अभ्यर्थियों द्वारा अवकाश के दिनों में भी निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने का यथासंभव प्रयास किया गया परन्तु शासकीय कार्यालय बन्द होने से वे दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को कार्यालयीन अवधि में कार्यालय खुलने पर प्रस्तुत करने में सफल हुए निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने के हरसंभव प्रयास के बाद शासकीय अवकाश पर कार्यालय बन्द होने के कारण

18 से 20 दिसम्बर 2015 के मध्य निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफलता उनके सामर्थ्य से परे थी। ऐसी स्थिति में अवकाश के ठीक अगली तारीख दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल कर अभ्यर्थियों ने कोई चूक नहीं की है। यदि आपत्तिकर्ता के इस कथन को कि दिनांक 19 दिसम्बर 2015 को निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करना था, तर्क के लिए सही मान लिया जाये तो भी जो अभ्यर्थियों के सामर्थ्य से परे हो उसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि परिसीमन अधिनियम, 1963 की धारा 4 में भी लेख है कि विहित काल का अवसान ऐसे दिन होता है जिस दिन न्यायालय बन्द हो वह उस दिन बाद संस्थित किया जा सकेगा जिस दिन न्यायालय फिर खुले। उक्त प्रावधान के अनुसार भी अभ्यर्थीगण श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती चमेली साहू एवं श्रीमती सुनीता देवांगन द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा समयसीमा में प्रस्तुत किया गया मान्य किया जाना न्यायोचित है।

8. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका), रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 20 अप्रैल 2016 एवं पत्र दिनांक 19.7.2016 में दिये गये अभिमत में लेख है कि उक्त जानकारी चूंकि निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की 30 दिनों की गणना के अनुसार समयसीमा का आखिरी दिन 18 दिसम्बर 2015 को शासकीय अवकाश, 19 दिसम्बर, 2015 को तृतीय शनिवार एवं उसके पश्चात 20 दिसम्बर 2015 को रविवार का शासकीय अवकाश होने के कारण कार्यालय का अगला कार्यकारी दिवस 21 दिसम्बर 2015 को होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 तक प्रस्तुत करना था। आयोग द्वारा जारी नगरपालिका निर्वाचन-निर्वाचन संदर्शिका वर्ष 2014 के अध्याय 19 के बिन्दु 7 (i) एवं (ii) लेखा दाखिल करने की अंतिम तारीख में निर्वाचन व्यय लेखा की निर्धारित 30 दिन की समयसीमा गणना के अनुसार "यदि समयसीमा की आखरी तारीख को सार्वजनिक अवकाश हो तो समयावधि उसके ठीक बाद के कार्यकारी दिन तक के लिए (अर्थात् अवकाश के बाद, जिस दिन कार्यालय खुले उस दिन तक के लिए) बढ़ी हुई मानी जाये।" के प्रावधान के अनुसार तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर पालिका) के अभिमत के अनुसार प्रश्नाधीन प्रकरण में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने की आखरी तारीख दिनांक 21 दिसम्बर 2015 मान्य किया जाना न्यायोचित है। क्योंकि दिनांक 19 दिसम्बर 2015 एवं 20 दिसम्बर 2015 को क्रमशः तृतीय शनिवार एवं रविवार का शासकीय अवकाश था।

9. अतः उपरोक्त विवेचना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अभ्यर्थियों श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती चमेली साहू एवं श्रीमती सुनीता देवांगन द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2015 को प्रस्तुत किया गया निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयसीमा में प्रस्तुत किया जाना मान्य किया जाता है। तदनुसार अभ्यर्थियों श्रीमती अम्बिका यदु, श्रीमती सीमा यादव, श्रीमती चमेली साहू एवं श्रीमती सुनीता देवांगन के विरुद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है।

अभ्यर्थीगण श्रीमती हलीमा खातून, श्रीमती शहिदा बेगम, श्रीमती जरीना बेगम, श्रीमती जैतून कुरैशी,

श्रीमती मोमिना खातून, श्रीमती सुमित्रा देवांगन एवं श्रीमती ललिता देवांगन को अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 5 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये नगर पालिक निगम के महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए।

18. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 31 जनवरी 2017 को जारी किया गया।

हस्ता./  
(राम सिंह)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त.